

श्री अरविन्द नेताम : अभी तक करीब 46 देशों—

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने दो शायदों में पूछा है ।

श्री अरविन्द नेताम : 1976 में करीब चार देशों से और 1975 में करीब आठ देशों से हुए हैं । अगर आप कहिये तो मैं उन देशों के नाम पढ़ दूँ ।

Revision in Ex-factory Prices of Sugar

*289. SHRI K. M. 'BADHUKAR':
SHRI D. D. DESAI:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the ex-factory prices of sugar, have been revised again recently; and

(b) if so, the prices increased and reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SHAHNAWAZ KHAN): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the Sabha. [Placed in Library. See No. LT-11297/76].

श्री कमला मिश्र 'बधुकर' : नीति के बारे में अगर मैं प्रश्न करूँ तो अध्यक्ष महोदय आप एकाउ नहीं करेंगे—

अध्यक्ष महोदय : सूचना दीजिये तो ।

श्री कमला मिश्र 'बधुकर' : हमारी सरकार की चीनी के बारे में जो नीति है वह दिन मालिकों को खुश करने की नीति है जहाँ तक कज्युमर्ज और किसानों का सम्बन्ध है सरकार की नीति बिल्कुल चातक नीति है । स्टेटमेंट में बताया गया है कि चूंकि यूरोप आफ इंडस्ट्रियल क्रस्ट्स एंड प्राईसिस की रिपोर्टेशन हो गई थी इसलिये चीनी की एक्स फैक्ट्री प्राईस बढ़ा दी है । इसको

बढ़ाने के बाद उपभोक्ता की सही दायों पर चीनी मिलाने के लिए धाप ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री शाहनवाज खाँ : लेवी शुगर की जो प्राईस है वह जो पहले थी यानी 2 रुपये 15 पैसे पर कितनी बढ़ बही रहेगी । उस चीनी की कीमत बढी नहीं है ।

श्री कमला मिश्र 'बधुकर' : चूंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में तमाम चीनी मिलें पुरानी पड़ गई है, उनकी मशीनरी पुरानी पड़ गई है क्या यह सही नहीं है कि उसकी वजह से शुगर की कास्ट प्राईस बढ़ जाती है, प्रोडक्शन कास्ट बढ़ जाती है ? अगर हाँ तो उन चीनी मिलों के नवीनीकरण के लिए तार्किक उनको कास्ट ग्राफ प्राइवशन घट मक और धापको दाम बढ़ाने का मौका न मिले, धाप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री शाहनवाज खाँ : ऐसी स्कीम गवर्नमेंट के जेरे गौर है ताकि पुरानी शुगर मिलों का मॉडर्नाइजेशन और रिहैबिलिटेशन हो सके । उनकी मशीनरी को नए सिरे से बेहतर बनाने के लिये गवर्नमेंट लोन वगैरह देने की बात भी मोच रही है ।

SHRI D. D. DESAI: The production of sugar has declined from 48 lakh tonnes to 42 lakh tonnes, and the export also has been affected to some extent. The statement laid on the Table of the House shows that the costing is done by the Bureau of Industrial Costs and Prices. May I know from the hon. Minister whether the variation between the lowest and the highest is nearly a hundred per cent? Can he not consider seeing that the cost element particularly. The crushing period recovery and sugarcane price are all arranged in a manner that the sugarcane growers do get a remunerative price which is presently a matter of great concern in the House and outside?

MR. SPEAKER: It is a different question about sugar cane price and not about the ex-factory price of sugar.

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: These are two different prices. .

MR. SPEAKER: The relevance in this is only whether, as a result of the ex-factory price of sugar being revised, the sugar cane prices will also be affected or what. That aspect you can answer. Otherwise, there is no relevance.

SHRI D D DESAI: The difference is of the order of 100 per cent between the lowest and the highest.

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: As you have very rightly remarked, these are two entirely different questions. One is fixation of the price of levy sugar and the other is fixation of the price of sugar cane. The price of sugar-cane is fixed on the recommendation of the Agricultural Prices Commission and the Central Government consults the States and the sugar-cane growers and then fixes the prices. The fixation of the price of levy sugar .

MR. SPEAKER Shri Ramavatar Shastrri

श्री रामावतार शास्त्री एक क्विंटल चीनी का उत्पादन खर्च कितना आता है और उसका विक्री मूल्य क्या होता है? दोनों को देखते हुए आप मिल मालिकों को कितना मुनाफा देने है और क्या उस मुनाफे में आप कमी करने का विचार रखते हैं हिन्दुस्तान की जनता की भावनाओं को देखते हुए?

श्री शाहनवाज खां : उन्होंने खर्च का सवाल पूछा है। उस में गन्ने की कीमत ही शामिल नहीं होती है और भी बहुत सी चीजें उस में आती हैं। लागत मूल्य को टरिफ कमिशन पहले और फिर ब्यूरो आफ इन्स्ट्रियल कांट्रोल एंड प्राइसिज दोनों

देखते हैं और जानकीन करके के बाव ही कोई सिफारिश करते हैं —

अध्यक्ष महोदय उन्होंने की पूछा है, वह इनफॉर्मेशन आपके पास है तो बता दें ?

श्री शाहनवाज खां : उसी पर मैं बत रहा हूँ। वे बर्क भाउट करते हैं कि उनकी 12.25 परसेंट से ज्यादा मुनाफा न होने पाए।

श्री रामावतार शास्त्री: कमी करने का विचार है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय होता तो वह देते ॥

श्री गंगा सिंह शृंगर कमिशन ने चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में अपनी रिपोर्ट के एक हिस्से में बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। लेकिन मैं उसके बारे में इस बात नहीं पूछता हूँ। हमारे हिस्से में उसने जो सिफारिश की थी उसके बारे में मैं पूछता हूँ। उसने नुमा सुझाव दिया था कि चीनी की कीमत तय करने के लिये बोर्ड बनाया जाय, साथ ही उसने यह कहा था कि क्रे के डिजल्पमेंट के लिये कुछ किया जाए इत्यादि। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने उन मामलों की तरफ से क्या आखे मूव नी है? क्या कोई भी काम उभ दिशा में नहीं किया है?

अध्यक्ष महोदय, गन्ने की उपज उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत कम होती है। फेक्ट्रियां वहाँ सब से ज्यादा हैं। सब से कम उपज हिन्दुस्तान भर में उत्तर प्रदेश और बिहार में ही होती है। क्या सरकार को इस पर कोई सिफारिश मिली थी? यदि हाँ, तो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की जिस से कम से कम दाम पर लोगों को शृंगर मिल सके?

अध्यक्ष महोदय. माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं कि शृंगर कमिशन की सिफारिशें क्यों नहीं मानी?

की जाहानवाज खां : यह हमने माना है कि सिवाय इसके कि जहाँ पर वह कोई राब काम नहीं कर सके। जहाँ पर उन की सिफारिशें बुनामिस थीं वह हमने मान ली हैं।

श्री नंदा शिंदे : क्या मंत्री जी ने ग्रामीणों से 'रपो' को देख लिया है जो भ्रमर बेचने और बलपमेंट के सिलमिले में उन्होंने बोर्ड बनाने की सिफारिश की थी, उस पर क्या पदाही हो रही है ?

श्री जाहानवाज खां : यह रिपोर्ट मैंने बहुत गौर के साथ गड़ी और भ्रमर केन डवलपमेंट के लिये जो जो उनकी सिफारिशों की उन पर हम काम कर रहे हैं। भ्रमर बेचने के बारे में जो एग्जैस रियलाइजेशन है उस पर जो किसानों को 50 परसेंट दिया जाय यह बात भी है।

SHRI DINEN BHATTACHARYA: May I know actually whether any percentage of this levy sugar is being exported and if so, what is the export price of it and how does it compare with the price that has been detailed here in Appendix I of the Statement?

MR. SPEAKER: Has it any relation with the export price?

SHRI SHAHNAWAZ KHAN No, Sir. The export prices were very very high. You know, Sir, that was 600 pounds per ton. That has come down.

Study of Rain Fed Cultivation of Black Cotton Soil

*270 **SHRI BHAGATRAM MANHAR:**

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY:

Will the Minister of **AGRICULTURE AND IRRIGATION** be pleased to state—

(a) whether Government propose to locate pilot projects to study the com-

plex problems arising in rain fed cultivation in black cotton soil in Narmada Valley; and

(b) if so, facts thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) and (b): No, Sir. There is no such proposal with the Government of India. It may, however, be mentioned that under a Centrally Sponsored Scheme of Integrated Dryland Agricultural Development, 6 pilot projects out of 24 are in operation since beginning of the Fourth Five Year in the black soil areas of Indore and Rewa (Madhya Pradesh), Solapur and Akola (Maharashtra) and Rajkot and Amreli (Gujarat); but none of these district from part of Narmada Valley.

श्री भगतराम मनहर : अभी कुछ देर पहले मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि कपास की पैदावार में काफी कमी है। कपास की पैदावार बढ़ाना देश और जनहित में है। नर्मदा घाटी की काली मिट्टी कपास की पैदावार के लिये बहुत अच्छी है और क्षेत्रफल भी काफी है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो आप ने प्रस्ताव दिया है कि इंटेंसिव प्रोग्राम बना रहे हैं कपास की पैदावार बढ़ाने के लिये क्या इस बारे में आप विचार करेंगे कि खाली इस प्रोग्राम से ही जितनी कपास की आवश्यकता है उस की पूर्ति नहीं होगी, बल्कि अतिरिक्त अमीन में भी कपास की खेती करने के लिये कोई योजना लागू करनी होगी। क्या मंत्री जी इस हेतु नर्मदा घाटी को प्राथमिकता देंगे ?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: The black-soil, whether it be in Narmada Valley or elsewhere, is more or less similar. After our experience here, it can be utilised in Narmada Valley as well.